



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 9, 2012/श्रावण 18, 1934

No. 179।

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 9, 2012/SHRAVANA 18, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2012

(निर्णायक समीक्षा)

विषय :— चीनी ताइपेई के मूल के या वहां से निर्यातित “नोनाइल फेनोल” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

फा. सं. 15/1007/2012-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में और उसके बाद यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीनी ताइपेई (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित “नोनाइल फेनोल” (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी।

(1) यतः प्राधिकारी द्वारा 29 जून, 2006 की अधिसूचना सं. 14/13/2005—डी जी ए डी के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में मूल जांच शुरू की थी। निश्चयात्मक शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हुए प्राधिकारी ने 25 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 14/13/2005—डी जी ए डी के तहत अंतिम जांच परिणाम संबंधी अधिसूचना जारी की थी। अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा 22 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. 94/2007—सी.शु. के तहत संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर दिनांक 22 अगस्त, 2007 से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

(2) यतः मैं एस आई ग्रुप इंडिया लि., थाणे, नवी मुंबई ने चीनी ताइपेई के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का आरोप लगाते हुए उक्त अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत पुष्टीकृत आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

(3) निर्णायक समीक्षा हेतु यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मैं एस आई ग्रुप इंडिया लि., थाणे, नवी मुंबई ने दायर किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है और इसलिए वे नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

(4) वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद नोनाइल फेनोल है, जिसे पैरा नोनाइल फेनोल के नाम से भी जाना जाता है। यह तलछट रहित साफ विस्कोस द्रव होता है। “नोनाइल फेनोल” का रासायनिक सूत्र और संरचना C15H24O है। इसका उपयोग कृषि रसायन तुस्खों हेतु स्नेहक तेलों तथा संघटकों में अपक्षरण निषेधकों के रूप में प्रयुक्त व्युत्पत्तियों के तेल में घुलनशीन फेनोलिक रेजिन के परवर्ती सल्फोनेशन के बाद गैर-आयनिक सरफैक्टेंट्स जैसे अनुप्रयोग के लिए एन पी-एथीलिन ऑक्साइट कंडेंसेटों के विनिर्माण में किया जाता है। इसका प्रयोग लौ-प्रतिरोधकों और प्लास्टिक साइजरों में भी किया जाता है।

(5) यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण के उपशीर्ष सं. 2907.13 के अंतर्गत वर्गीकृत है। आवेदक ने यह बताया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात 2907.1190, 2907.2990, 3204.1790, 3810, 9090, 2921, 4590, 2909, 5090, 3403, 1900, 3402, 1300, और 3402, 1900 जैसे कई अन्य सीमाशुल्क वर्गीकरणों में भी किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के क्षेत्र पर किसी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

(6) दायर किए गए विधिवत पुष्टीकृत आवेदन को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में लागू शुल्क को निरंतर लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने कि क्या ऐसे शुल्क की सम्भावना से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, के लिए एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं।

शामिल देश

(7) संबद्ध जांच में शामिल देश चीनी ताइपेई है।

जांच अवधि

(8) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 (12 माह) तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा जांच अवधि शामिल होंगे।

प्रक्रिया

(9) वर्तमान निर्णायक समीक्षा में दिनांक 25 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 14/13/2005-डी जी ए डी के तहत प्रकाशित मूल जांच के अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल हैं।

(10) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध इस समीक्षा में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

सूचन प्रस्तुत करना

(11) संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, संबद्ध देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के जरिए उसकी सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों तथा प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग,

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

(12) कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध भी कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

समय—सीमा

(13) वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है और प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

(14) सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

(15) यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग सेटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ सं. आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए।

(16) किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। समस्त हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय रूपांतरण को दो (2) प्रतियां और अगोपनीय रूपांतरण की पांच (5) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(17) गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।

(18) अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

(19) प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने के अनिच्छुक हैं तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

(20) सार्वजनिक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

(21) नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

(22) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है और उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उसके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2012

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed on imports of 'Nonyl Phenol' originating in or exported from Chinese Taipei.

F. No. 15/1007/2012-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and thereafter (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of anti-dumping duty on imports of 'Nonyl Phenol' (hereinafter referred as the subject goods), originating in or exported from Chinese Taipei (hereinafter referred to as the subject country).

1) WHEREAS, the original investigation concerning imports of the subject goods from the subject country was initiated by the Authority vide Notification No. 14/13/2005-DGAD dated 29th June 2006. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide notification No.14/13/2005-DGAD dated 25th June 2007, recommending imposition of definitive duty. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed w.e.f. 22nd August, 2007 by the Department of Revenue vide Notifications No. 94/2007-Customs dated 22nd August, 2007 on the imports of the of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2) Whereas, M/s. S.I Group India Limited, Thane, Navi Mumbai has filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the producers of the subject goods in India, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from Chinese Taipei and consequent injury to the domestic industry and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2971 40712-2

Domestic Industry

3) The application for the sunset review has been filed by M/s. S.I Group India Limited, Thane, Navi Mumbai on behalf of the domestic industry. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article

4) The product under consideration in the present application is Nonyl Phenol, which is also known as Para Nonyl Phenol. It is a clear viscous liquid without sediments. The chemical formula and structure of Nonyl Phenol is C₁₅H₂₄O. It is used in the manufacture of NP-ethylene oxide condensates for application as non-ionic surfactants after subsequent sulphonation, of oil soluble phenolic resin, of derivatives applied as corrosion inhibitors in lubricating oils and of ingredients for agro-chemical formulations. It is also used in flame-retardants and plasticizers.

5) The product is classified under sub-heading no. 2907.13 under Customs Tariff Act and Indian Trade Classification. The applicant has stated that the subject goods are also imported from the subject country under various other Customs classifications such as 2907.1190, 2907.2990, 3204.1790, 3810,9090, 2921,4590, 2909,5090, 3403,1900, 3402,1300, and 3402,1900. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

Initiation of Sunset Review

6) In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved

7) The country involved in the subject investigation is Chinese Taipei.

Period of Investigation

8) The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 and the POI.

Procedure

9) The present sunset review covers all aspects of the final findings of the original investigation published vide Notification No.14/13/2005-DGAD dated 25th June 2007.

10) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information

11) The known exporters in the subject country, the Government of the subject country through their Economic and Cultural Centre, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

12) Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

13) Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

14) All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Anti-dumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis

15) In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16) Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

17) For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18) The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

19) The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20) Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

21) In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

22) In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority